



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3706]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 2019/कार्तिक 24, 1941

No. 3706]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 2019/KARTIKA 24, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

**का.आ.4128(अ).—**राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

**आदेश**

28 अक्टूबर, 2019

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए एक निर्देश तारीख 7 अप्रैल, 2017 को इस प्रश्न पर किया गया था कि, क्या श्री संजीव झा और 10 अन्य, दिल्ली विधान सभा के सदस्य लाभ का पद धारण करने के लिए निरहित होने चाहिए;

और, यह निर्देश श्री विवेक गर्ग, अधिवक्ता और आरटीआई सक्रियतावादी, शक्ति नगर, दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् “याची” कहा गया है) द्वारा तारीख 17 मार्च, 2017 को फाइल किए गए अभ्यावेदन से उद्भूत हुआ है, जिसमें निम्नलिखित दिल्ली विधान सभा सदस्यों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “प्रत्यर्थी” कहा गया है) की निरर्हता चाही गई है:

1. श्री संजीव झा, (एसी-2, बुराड़ी)
2. श्री नितिन त्यागी, (एसी-58, लक्ष्मी नगर)
3. श्री प्रवीण कुमार, (एसी-41, जंगपुरा)
4. श्री पवन कुमार शर्मा, (एसी-4, आदर्श नगर)

5. श्री दत्त शर्मा, (एसी-66, घोण्डा)
6. श्री राजेश गुप्ता, (एसी-17, वजीरपुर)
7. श्रीमती सरिता सिंह, (एसी-64, रोहताश नगर)
8. श्री दिनेश मोहनिया, (एसी-49, संगम विहार)
9. श्री अमानतुल्लाह खान, (एसी-54, ओखला)
10. श्री कैलाश गहलोत, (एसी-35, नजफगढ़)
11. श्री जरनैल सिंह, (एसी-29, तिलक नगर)

और, याची ने यह अभिकथन किया है कि उपरोक्त नामित विधान सभा सदस्य दिल्ली के ग्यारह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण [डीडीएमए] में सह-अध्यक्ष का पद लेने पर “लाभ का पद” धारण करने के लिए निरहित होने के दायी हैं। याची ने यह निवेदित किया है कि एक एम.एल.ए. डीडीएमए के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारत का संविधान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कार्य संचालन नियम, 1993 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कार्य आबंटन नियम में नहीं है जो इसे उपबंधित या अनुज्ञात करे और इसके बावजूद प्रत्यर्थियों ने डीडीएमए में सह-अध्यक्ष का पद विधिविरुद्धता धारण किया है जो कि लाभ का पद की परिभाषा के अन्तर्गत आता है;

और आयोग ने तारीख 04.05.2017 के पत्र द्वारा इस संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव से कतिपय जानकारी मांगी थी। आयोग के प्रश्न के उत्तर में जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) के कार्यालय ने तारीख 20.06.2017 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीडीएमए)/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर-पश्चिम जिला ने तारीख 22.06.2017 के पत्र द्वारा प्रत्युत्तर दिया जो आयोग को 06.07.2017 को प्राप्त हुआ था, और विशेष सचिव (डीएम) राजस्व विभाग (एचक्यू), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तारीख 19.09.2017 के पत्र द्वारा प्रत्युत्तर दिया जो आयोग को 21.09.2017 को प्राप्त हुआ था;

और, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार ने उपरोक्त उल्लिखित सभी उत्तरों में यह निवेदित किया कि डीडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन जारी अधिसूचना तारीख 19.01.2015 और अधिसूचना तारीख 29.04.2015 द्वारा हुई है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार ने यह और जानकारी दी कि डीडीएमए का सह-अध्यक्ष न तो वेतन, भत्ते, बैठक फीस आदि के माध्यम से किसी पारिश्रमिक का, और न ही स्टाफ कार/परिवहन भत्ते आदि जैसी अन्य किसी सुविधा का हकदार है। इसके अतिरिक्त किसी कार्यालय स्थान, समर्थक स्टाफ, निवास, टेलीफोन या कैप कार्यालय का भी कोई उपबंध नहीं है;

दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हताओं को हटाना) अधिनियम, 1997, अधिनियम की अनुसूची में विहित कतिपय पदों के संबंध में “लाभ के पद” धारण करने से उद्भूत होने वाली निरर्हता को हटाने का उपबंध करता है। अनुसूची के मद 14 में अध्यक्ष, निदेशक या किसी कानूनी या गैर-कानूनी निकाय या समिति या निगम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा गठित सोसाइटी के किसी सदस्य के पद के लिए छूट का उपबंध है, परंतु यह कि अध्यक्ष, निदेशक या उपरोक्त बोर्ड या निकाय का कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा;

और, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार से प्राप्त प्रत्युत्तरों जैसा कि उपरोक्त नोट किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि डीडीएमए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा गठित एक कानूनी निकाय है और इसके सह-अध्यक्ष किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं ;

और, निर्वाचन आयोग ने यह संप्रेक्षित किया है कि डीडीएमए में सह-अध्यक्ष का पद दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1997 की अनुसूची के मद 14 के अनुसार छूट प्राप्त प्रवर्ग में आता है और इसलिए आयोग ने दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन अपनी राय (उपाबंध के द्वारा) दी है कि प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हित नहीं है;

अतः, अब, मैं, रामनाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूँ कि उपरोक्त नामित श्री संजीव झा और 10 अन्य, दिल्ली विधान सभा के सदस्य "लाभ का पद" धारण करने के लिए निरर्हित नहीं हैं।

28 अक्तूबर, 2019 ।

**भारत के राष्ट्रपति**

### **राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध**

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

### **2017 का निर्देश मामला सं. 3(पी)**

**[भारत के राष्ट्रपति से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991**

### **की धारा 15(4) के अधीन निर्देश]**

*संदर्भ : 2017 का निर्देश मामला सं. 3(पी) – भारत के माननीय राष्ट्रपति से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ जिसमें निर्वाचन आयोग से श्री संजीव झा और 10 अन्य, दिल्ली विधान सभा के सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) के अधीन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सह-अध्यक्ष का पद लेने पर "लाभ का पद" धारण करने के लिए राय मांगी गई है।*

### **राय**

1. यह तारीख 07.04.2017 का निर्देश है जो भारत के माननीय राष्ट्रपति से 10.04.2017 को प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग से श्री विवेक गर्ग, अधिवक्ता और आरटीआई सक्रियतावादी, शक्ति नगर, दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) द्वारा 17.03.2017 को फाइल किए गए अभ्यावेदन पर निम्नलिखित दिल्ली विधान सभा सदस्यों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है) की चाही गई निरर्हता पर राय मांगी गई है :

1. श्री संजीव झा, (एसी-2, बुराड़ी)
2. श्री नितिन त्यागी, (एसी-58, लक्ष्मी नगर)
3. श्री प्रवीण कुमार, (एसी-41, जंगपुरा)
4. श्री पवन कुमार शर्मा, (एसी-4, आदर्श नगर)

5. श्री दत्त शर्मा, (एसी-66 घोण्डा)
6. श्री राजेश गुप्ता, (एसी-17, वजीरपुर)
7. श्रीमती सरिता सिंह, (एसी-64, रोहताश नगर)
8. श्री दिनेश मोहनिया, (एसी-49, संगम विहार)
9. श्री अमानतुल्लाह खान, (एसी-54, ओखला)
10. श्री कैलाश गहलोत, (एसी-35 नजफगढ़)
11. श्री जरनैल सिंह, (एसी- 29 तिलक नगर)

2. याची ने यह अभिकथन किया है कि उपरोक्त नामित विधान सभा सदस्य दिल्ली के ग्यारह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात 'डीडीएमए' कहा गया है) में सह-अध्यक्ष का पद लेने पर "लाभ का पद" धारण करने के लिए निर्हित होने के दायी हैं। याची ने यह निवेदित किया है कि एक एम.एल.ए. डीडीएमए के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारत का संविधान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कार्य संचालन नियम, 1993 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कार्य आबंटन नियम में नहीं है जो इसे उपबंधित या अनुज्ञात करे और इसके बावजूद प्रत्यर्थियों ने डीडीएमए में सह-अध्यक्ष का पद विधिविरुद्धतया धारण किया है जो कि लाभ का पद की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

3. आयोग ने पत्र सं. 113/3(पी)/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसी/जेयूडी/2017/रजिस्ट्री/611 तारीख 04.05.2017 द्वारा इस संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव से कतिपय जानकारी मांगी थी। आयोग के पत्र के उत्तर में जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) के कार्यालय ने पत्र सं. एफ. सं. डीसी(एन)/डीडीएमए/आरटीआई/2012-13/1499 तारीख 20.06.2017 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीडीएमए)/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर-पश्चिम जिला ने तारीख 22.06.2017 के पत्र द्वारा प्रत्युत्तर दिया जो आयोग को 06.07.2017 को प्राप्त हुआ था और विशेष सचिव (डीएम) राजस्व विभाग (एचक्यू), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पत्र एफ.सं.1(302)/डीडीएमए (एचक्यू) निर्वाचन आयोग-विवेक/2017/88 तारीख 19.09.2017 के पत्र द्वारा प्रत्युत्तर दिया जो आयोग को 21.09.2017 को प्राप्त हुआ था।

4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार ने उपरोक्त उल्लिखित सभी उत्तरों में यह निवेदित किया कि डीडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन जारी अधिसूचना सं. एफ.1(25)/डीडीएमए (एचक्यू)/डीडीएमए-नियम/2013/पीएफ-1/52-74 तारीख 19.01.2015 और अधिसूचना सं. एफ. 1(37)/डीडीएमए(एचक्यू)/डीडीएमए/आरएफ-1/2015/172 तारीख 29.04.2015 द्वारा हुई है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार ने यह और जानकारी दी कि डीडीएमए का सह-अध्यक्ष न तो वेतन, भत्ते, बैठक फीस आदि के माध्यम से किसी पारिश्रमिक का और न ही स्टाफ कार/ परिवहन भत्ते आदि जैसी अन्य किसी सुविधा का हकदार है। इसके अतिरिक्त, किसी कार्यालय स्थान, समर्थक स्टाफ, निवास, टेलीफोन या कैंप कार्यालय का भी कोई उपबंध नहीं है।

5. दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरहताओं को हटाना) अधिनियम, 1997, अधिनियम की अनुसूची में विहित कतिपय पदों के संबंध में "लाभ के पद" धारण करने से उद्भूत होने वाली निरहता को हटाने का उपबंध करता है। अनुसूची के मद 14 में अध्यक्ष, निदेशक या किसी कानूनी या गैर-कानूनी निकाय या समिति या निगम या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा गठित सोसाइटी के किसी सदस्य के पद की छूट का उपबंध है, परंतु यह कि अध्यक्ष, निदेशक या उपरोक्त बोर्ड या निकाय का कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

6. प्रत्यर्थी, सभा निर्वाचन-क्षेत्र सं.38, दिल्ली छावनी का सदस्य होने पर, जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) के क्षेत्र में आता है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (जिसमें इसमें इसके पश्चात्, "1994 का एनडीएमसी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4(1)(ख) के अनुसार एनडीएमसी का सदस्य भी है।

7. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार से प्राप्त प्रत्युत्तरों जैसा कि उपरोक्त नोट किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि डीडीएमए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा गठित एक कानूनी निकाय है और इसके सह-अध्यक्ष किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं है।

8. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह संप्रेक्षित किया गया है कि डीडीएमए में सह-अध्यक्ष का पद दिल्ली विधान सभा सदस्य (निरर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1997 की अनुसूची के मद 14 के अनुसार छूट प्राप्त प्रवर्ग में आता है और इसलिए आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन अपनी राय (उपाबंध के द्वारा) दी है कि प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हित नहीं है;

ह0/-

(अशोक लवासा)  
(निर्वाचन आयुक्त)

ह0/-

(सुनील अरोड़ा)  
(मुख्य निर्वाचन आयुक्त)

ह0/-

(सुशील चन्द्रा)  
(निर्वाचन आयुक्त)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26.08.2019

[फा.सं.एच-11026/2/2019-वि.2]

डॉ.रीटा बशिष्ठ,अपर सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2019

**S.O. 4128 (E).**— The following Order made by the President is published for general information:-

### ORDER

28th October, 2019

Whereas a reference on the 7th April, 2017 was made seeking the opinion of the Election Commission under section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question whether Shri Sanjeev Jha and 10 Others, Members of the Legislative Assembly, Delhi should be disqualified for holding Office of Profit;

And whereas the reference arises in pursuance of the representation dated 17th March, 2017 filed by Shri Vivek Garg, Advocate & RTI Activist, Shakti Nagar, Delhi (hereinafter referred to as "Petitioner"), seeking disqualification of the following Members of the Delhi Legislative Assembly (hereinafter referred to as "Respondent"):

1. Shri Sanjeev Jha, (AC-2, Burari)
2. Shri Nitin Tyagi, (AC-58, Laxmi Nagar)
3. Shri Praveen Kumar, (AC-41, Jangpura)
4. Shri Pawan Kumar Sharma, (AC-4, Adarsh Nagar)
5. Shri Dutt Sharma, (AC-66, Ghonda)
6. Shri Rajesh Gupta, (AC-17, Wazirpur)
7. Smt. Sarita Singh, (AC-64, Rohtash Nagar)
8. Shri Dinesh Mohania, (AC-49, Sangam Vihar)
9. Shri Amanatullah Khan, (AC-54, Okhla)
10. Shri Kailash Gahlot, (AC-35, Najafgarh)
11. Shri Jarnail Singh, (AC-29, Tilak Nagar)

And whereas the Petitioner has alleged that the above named MLAs are liable to be disqualified for holding “Office of Profit” by occupying the office of Co-Chairperson in District Disaster Management Authorities [DDMA] in eleven Districts of Delhi. The Petitioner has submitted that an MLA cannot be appointed as Co-Chairperson of DDMA as there is no provision in the Disaster Management Act, 2005; the Constitution of India; the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991; Transaction of Business of the Government of National Capital Territory of Delhi Rules, 1993; and the Allocation of Business Rules of Government of National Capital Territory of Delhi which provides or permits the same and in spite of this the Respondents have unlawfully occupied the office of Co-Chairperson in DDMA which falls under the definition of Office of Profit;

And whereas the Commission vide letter dated 04.05.2017 had sought certain information in this regard from the Chief Secretary of the NCT of Delhi. In reply to the Commission’s query, the Office of the District magistrate (North) had responded vide letter dated 20.06.2017 and Chief Executive Officer (DDMA)/Additional District Magistrate, North – West District had responded vide letter dated 22.06.2017 which was received at the Commission on 06.07.2017 and the Special Secretary (DM) of Revenue Department (HQ), Delhi Disaster Management Authority has responded vide letter dated 19.09.2017 which was received at the Commission on 21.09.2017;

And whereas in all the above noted replies, the Government of NCT of Delhi has submitted that the DDMA has been established vide notification dated 29.04.2015 and notification dated 19.01.2015 issued under section 25 of the Disaster Management Act, 2005. The Government of National Capital Territory of Delhi has further informed that the Co-Chairperson of DDMA is neither entitled to any remuneration by way of salary, allowances, sitting fee etc. nor any other facility like staff car/transportation allowance etc. Moreover, there is also no provision for office space, supporting staff, residence, telephone or camp office;

And whereas the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 provides for the removal of the disqualification arising out of holding Office of Profit in respect of certain offices prescribed in the Schedule of the Act. Item 14 of the Schedule provides for the exemption of the office of the Chairman, Director or Member of a statutory or non-statutory body or committee or corporation or society constituted by the Government of NCT of Delhi, provided that the Chairman, Director or Member of any of the aforesaid Board or Body shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

And whereas in view of the replies received from the Government of National Capital Territory of Delhi as noted above, the Election Commission has made it clear that the DDMA is a statutory body constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi and its Co-Chairpersons are not entitled to any remuneration;

And whereas the Election Commission observed that the office of Co-Chairperson in DDMA falls under the exempted category as per item 14 of the Schedule of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 and therefore the Commission has tendered its opinion (vide Annexure) under section 15 (4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 that the Respondents are not disqualified for holding of Office of Profit;

Now, therefore, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby decide that Shri Sanjeev Jha and 10 Others above named Members of the Legislative Assembly of Delhi are not disqualified for holding of Office of Profit.

28th October, 2019.

PRESIDENT OF INDIA

## ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

## REFERENCE CASE NO. 3(P) OF 2017

**[Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991]**

*In ref: Reference Case No. 3 (P) of 2017 - Reference received from the Hon'ble President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of Shri. Sanjeev Jha and 10 others, Members of the Delhi Legislative Assembly, under Section 15(1)(A) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 for holding 'Office of Profit' by occupying the office of Co-Chairperson in District Disaster Management Authorities.*

## OPINION

1. This is a reference dated 07.04.2017 seeking 'opinion' of the Election Commission of India, which was received from the Hon'ble President of India on 10.04.2017 under Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 on the representation dated 17.03.2017 filed by Shri Vivek Garg, Advocate & RTI Activist, Shakti Nagar, Delhi (hereinafter referred to as 'the Petitioner'), seeking disqualification of the following Members of Delhi Legislative Assembly (hereinafter referred to as 'the Respondents'):

  1. Shri Sanjeev Jha, (AC-2, Burari)
  2. Shri Nitin Tyagi, (AC-58, Laxmi Nagar)
  3. Shri Praveen Kumar, (AC-41, Jangpura)
  4. Shri Pawan Kumar Sharma, (AC-4, Adarsh Nagar)
  5. Shri Dutt Sharma, (AC-66, Ghonda)
  6. Shri Rajesh Gupta, (AC-17, Wazirpur)
  7. Smt. Sarita Singh, (AC-64, Rohtash Nagar)
  8. Shri Dinesh Mohania, (AC-49, Sangam Vihar)
  9. Shri Amanatullah Khan, (AC-54, Okhla)
  10. Shri Kailash Gahlot, (AC-35, Najafgarh)
  11. Shri Jarnail Singh, (AC-29, Tilak Nagar)

2. The Petitioner has alleged that the above named MLAs are liable to be disqualified for holding "Office of Profit" by occupying the office of Co-Chairperson in District Disaster Management Authorities (hereinafter referred to as 'DDMA') in eleven Districts of Delhi. The Petitioner has submitted that an MLA cannot be appointed as Co-Chairperson of DDMA as there is no provision in the Disaster Management Act, 2005; the Constitution of India; the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991; Transaction of Business of the Government of National Capital Territory of Delhi Rules, 1993; and the Allocation of Business Rules of Government of National Capital Territory of Delhi which provides or permits the same and in spite of this the Respondents have unlawfully occupied the office of Co-Chairperson in DDMA- which falls under the definition of Office of Profit.
3. The Commission vide letter No. 113/3(P)/ECI/LET/FUNC/JUD/ 2017/Registry/611 dated 04.05.2017 dated 04.05.2017 had sought certain information in this regard from the Chief Secretary of the NCT of Delhi. In reply to the Commission's query, the Office of the District Magistrate (North) had responded vide letter bearing F.No. DC(N)/DDMA/RTI/2012-13/1499 dated 20.06.2017 and Chief Executive Officer (DDMA)/Additional District Magistrate, North – West District had responded vide letter dated 22.06.2017 which was received at the Commission on 06.07.2017 and the Special Secretary (DM) of Revenue Department (HQ), Delhi Disaster Management Authority has responded vide letter bearing F.No. 1(302)/DDMA(HQ)/Election Commission-Vivek/2017/88 dated 19.09.2017 which was received at the Commission on 21.09.2017.

4. In all the above noted replies, the Government of NCT of Delhi has submitted that the DDMA has been established *vide* Notification No. F. 1(37)/DDMA(HQ)/DDMA/RF1/2015/172 dated 29.04.2015 and Notification No. F. 1(25)/DDMA(HQ)/DDMA-Rules/2013/PF-I/52-74 dated 19.01.2015 issued under section 25 of the Disaster Management Act, 2005. The Government of National Capital Territory of Delhi has further informed that the Co-Chairperson of DDMA is neither entitled to any remuneration by way of salary, allowances, sitting fee etc. nor any other facility like staff car/transportation allowance etc. Moreover, there is also no provision for office space, supporting staff, residence, telephone or camp office.
5. The Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 provides for the removal of the disqualification arising out of holding Office of Profit in respect of certain offices prescribed in the Schedule of the Act. Item 14 of the Schedule provides for the exemption of the office of the Chairman, Director or Member of a statutory or non-statutory body or committee or corporation or society constituted by the Government of NCT of Delhi, provided that the Chairman, Director or Member of any of the aforesaid Board or Body shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance.
6. The Respondent, being a member of assembly constituency No. 38 Delhi Cantonment, which falls in the area of New Delhi Municipal Council (NDMC), is also a member of NDMC as per Section 4(1)(b) of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (hereinafter, "*NDMC Act of 1994*").
7. In view of the replies received from the Government of National Capital Territory of Delhi as noted above, it is clear that the DDMA is a statutory body constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi and its Co-Chairpersons are not entitled to any remuneration.
8. In view of the above, the Election Commission observed that the office of Co-Chairperson in DDMA falls under the exempted category as per item 14 of the Schedule of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 and therefore the Commission has tendered its opinion (*vide* Annexure) under section 15 (4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 that the Respondents are not disqualified for holding of Office of Profit.

-sd-

(Ashok Lavasa)

**Election Commissioner**

-sd-

(Sunil Arora)

**Chief Election Commissioner**

-sd-

(Sushil Chandra)

**Election Commissioner**

Place: New Delhi

Date: 26.08.2019

[F.No.H-11026/2/2019-Leg.II]

Dr.REETA VASHISTHA, Addl. Secy.